

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 1972/कार्तिक 2, 1894

No. 463]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 1972/KARTIKA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi. the 24th October 1972

**S.O. 678/18A/IDRA/72.**—Whereas the Central Government is of the opinion that Messrs. Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Garden Reach Workshops Limited, Calcutta (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely Messrs. Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order,
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 1(92)/71-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

**औद्योगिक विकास मंत्रालय**  
**(औद्योगिक विकास विभाग)**

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1972

का० आ० 678(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स कार्टर पुलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता औद्योगिक उपक्रम का जिसकी वास्तव उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया गया है, प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो लोक हित के लिए बहुत हानिकार है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गार्डेन रीच वर्कशापस् लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को उक्त उपक्रम, अर्थात् मैसर्स कार्टर पुलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता का पूर्ण प्रबन्ध, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (i) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ।
- (ii) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए पद धारण करेगा ।
- (iii) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझ तो, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति पहले ही समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 1(92)/71-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।